23-09-2020

अत्याधुनिक तकनीक से चीनी मिलों में घटाएं प्रदूषण

चीनी मिलों में प्रदूषण कम करने को बनाया जाए पर्यावरण प्रकोष्ठ

(आज समाचार सेवा)

कानपुर, 22 सितम्बर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान की ओर से ईटीपी ऑपरेशन एड एन्फ्लुएट एनालिसेस विषय पर आनलाइन तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ का उदघाटन करते हुए शर्करा एव प्रशासन, संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने चीनी मिलों से आह्वान किया कि वे समाज और पर्यावरण के हित में चीनी मिलों से निकलने वाले दूषित जल को शोधित (ट्रीटमेंट) करने हेतु आवश्यक कदम उठाये। उन्होंने कहाकि चीनी मिलों को स्वयं पर लगे प्रदूषित उद्योग के टैग को वर्ष 2030 तक हर कीमत पर हटाना होगा। इसके लिए शुद्ध जल की कम से कम खपत और प्रदूषित जल का कम से कम निकासी करना होगा। इसके साथ ही चीनी मिलों को अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए जल की खपत को कम करना भी आवश्यक होगा। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने कहा कि चीनी मिलों में गन्ने की प्रतिटन पेराई के दौरान 10 से 12 लीटर साफ पानी का उपयोग होता है, इसे दस फीसदी और कम किया जा सकता है। छोटे-छोटे ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कर दूषित जल की गुणवत्ता के अनुसार शोधित कर उसका दूसरा उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहाकि विविध इकाइयों में आवश्यकतानुसार छोटे-छोटे शोधन संयंत्र (ट्रीटमेंट प्लांट) की स्थापना करके दूषित जल उसकी गुणवत्ता के अनुसार शोधित ट्रीटमेंट करके रिसाइकिल करना चाहिये न कि उसे मुख्य शोधन संयत्र में भेजने की आवश्यकता है। विविध हीट एक्सचेंजर्स द्वारा उत्पादित सरप्लस कंडेंसेट को वांछित शोधन के उपरांत रिसाइकिल किया जा सकता है। निदेशक ने कहाकि चीनी मिलों में प्रदूषण को कम करने हेतु नियंत्रण करने के लिए पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाये जाने की जरूत है।

वेबिनार में शामिल निदेशक नरेन्द्र मोहन व अन्य।

एनएसआई में हुई ई-वेबिनार में विशेषज्ञों ने दिये व्याख्यान

चीनी मिलों के दूषित जल के शोधन के लिए

जरूरी कदम उठाये शर्करा उद्योग

सहारा न्यूज ब्यूरो

कानपुर।

भारत सरकार के संयुक्त सचिव (शर्करा एवं प्रशासन) सुबोध कुमार सिंह ने कहा है कि समाज एवं पर्यावरण हित में शर्करा उद्योग चीनी मिलों से निकलने वाले दूषित जल के शोधन के लिए आवश्यक उपाय करें। उन्होंने कहा कि यह हम सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम स्वच्छ व हरित चीनी उद्योग की स्थापना हेतु आधुनिक तकनीकी आविष्कारों की मदद से सार्थक प्रयास किया जाये। उन्होंने सभी से वर्ष 2030 तक चीनी उद्योग पर लगे प्रदूषित उद्योग के टैग को हटाने में सहयोग की अपेक्षा की।

आईएएस सुबोध कुमार सिंह राष्ट्रीय शर्करा संस्थान द्वारा ' ईटीपी आपरेशन एंड इफ्लुएंट एनालाइसिस' विषय पर आयोजित ऑनलाइन तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम संयोजक अनूप कुमार कनौजिया ने प्रतिभागियों को थीम से अवगत कराया।

नरेंद्र मोहन

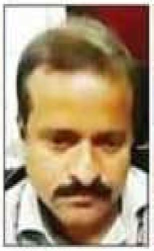

सुबोध सिंह

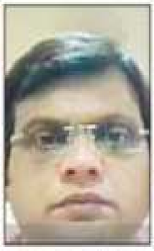

अनूप कुमार कनौजिया

जय प्रकाश श्रीवास्तव

राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम

मिलों में प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण प्रकोष्ठ बनाने पर दिया जोर

शर्करा संस्थान निदेशक प्रो.नरेन्द्र मोहन ने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग कर चीनी मिलों में ताजे पानी के खपत को 10 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। इससे अनुमानतः प्रति वर्ष 30 मिलियन लीटर पानी की बचत हो सकती है। उन्होंने चीनी मिलों में प्रदूषण को कम करने हेतु नियंत्रण के लिए ' पर्यावरण प्रकोष्ठ' बनाये जाने की जरूरत पर भी बल दिया। सलाहकार जेपी श्रीवास्तव ने चीनी मिलों में 'ऑनलाइन कंटीन्यूअस इमिशन एंड इफ्लूएंट मॉनीटरिंग सिस्टम' की स्थापना पर विशेष जोर दिया। संस्थान के डॉ. विष्णु प्रभाकर (सहायक आचार्य, कार्बनिक रसायन) ने विभिन्न गुणवत्ता मापदंडों के विश्लेषण के दौरान स्टैण्डर्ड प्रोटोकॉल द्वारा विश्लेषण की नवीनतम विधियों के संबंध में जानकारी दी।

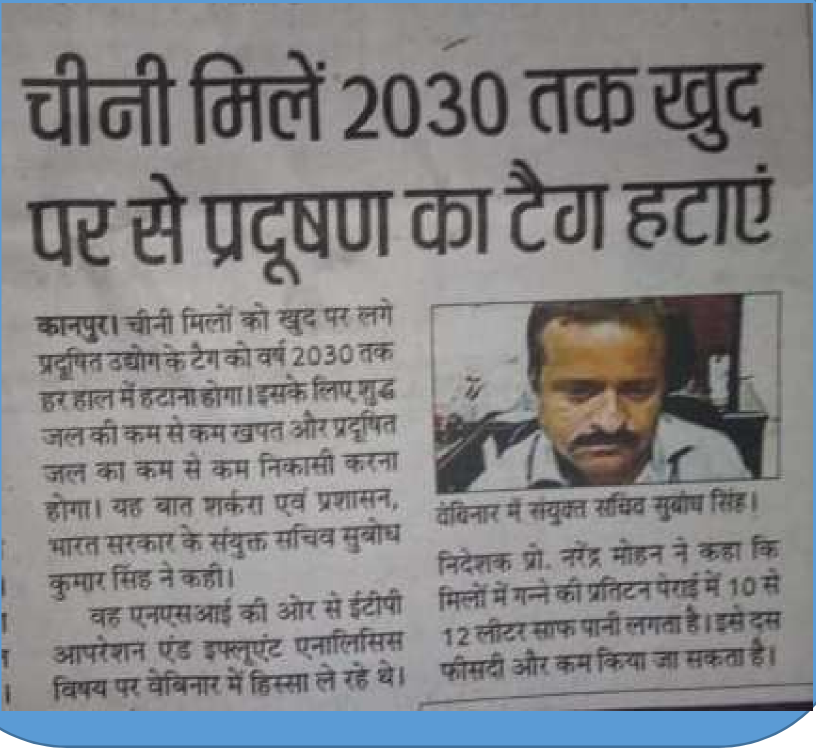

चीनी मिलें 2030 तक खुद पर से प्रदूषण का टैग हटाएं

कानपुर। चीनी मिलों को खुद पर लगे प्रदूषित उद्योग के टैग को वर्ष 2030 तक हर हाल में हटाना होगा। इसके लिए शुद्ध जल की कम से कम खपत और प्रदूषित जल का कम से कम निकासी करना होगा। यह बात शर्करा एवं प्रशासन, भारत सरकार के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कही।

वह एनएसआई की ओर से ईटीपी आपरेशन एंड इफ्लूएंट एनालिसिस विषय पर वेबिनार में हिस्सा ले रहे थे।

वेबिनार में संयुक्त सचिव सुबोध सिंह।

निदेशक प्रो. नरेंद्र मोहन ने कहा कि मिलों में गन्ने की प्रतिटन पेराई में 10 से 12 लीटर साफ पानी लगता है। इसे दस फीसदी और कम किया जा सकता है।

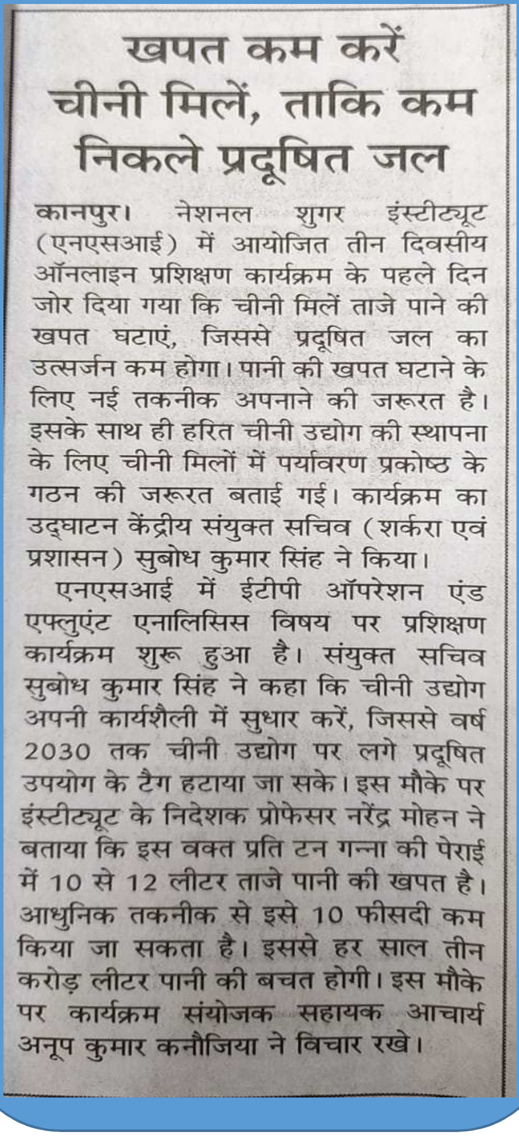

खपत कम करें चीनी मिलें, ताकि कम निकले प्रदूषित जल

कानपुर। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट (एनएसआई) में आयोजित तीन दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन जोर दिया गया कि चीनी मिलें ताजे पाने की खपत घटाएं, जिससे प्रदूषित जल का उत्सर्जन कम होगा। पानी की खपत घटाने के लिए नई तकनीक अपनाने की जरूरत है। इसके साथ ही हरित चीनी उद्योग की स्थापना के लिए चीनी मिलों में पर्यावरण प्रकोष्ठ के गठन की जरूरत बताई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय संयुक्त सचिव (शर्करा एवं प्रशासन) सुबोध कुमार सिंह ने किया।

एनएसआई में ईटीपी ऑपरेशन एंड एफ्लुएंट एनालिसिस विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि चीनी उद्योग अपनी कार्यशैली में सुधार करें, जिससे वर्ष 2030 तक चीनी उद्योग पर लगे प्रदूषित उपयोग के टैग हटाया जा सके। इस मौके पर इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने बताया कि इस वक्त प्रति टन गन्ना की पेराई में 10 से 12 लीटर ताजे पानी की खपत है। आधुनिक तकनीक से इसे 10 फीसदी कम किया जा सकता है। इससे हर साल तीन करोड़ लीटर पानी की बचत होगी। इस मौके पर कार्यक्रम संयोजक सहायक आचार्य अनूप कुमार कनौजिया ने विचार रखे।